Malhotra Committee Recommendations without Civic Agencies

558. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that none of the architecture and planning departments in the civic agencies represented in the deliberations of the V.K. Malhotra Committee entrusted with the task of framing unified building bye-laws;

(b) if so, the reasons for not including the civic agencies; and

(c) how does Government think that building bye-laws framed under such circumstances would serve any propose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

नागरिकों के लिए सस्ते आवास

559. श्री ओंकार सिंह लखावत: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के लोगों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने की विशेष योजना प्रारम्भ कर रही है;

(ख) वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान कितनी रिहायशी इकाइयों का निर्माण करने और आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1998-99 में राजस्थान में कितनी रिहायशी इकाइयां बनाने का प्रस्ताव है और सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) चूंकि आवास राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें मुख्यत:, सांस्थानिक वित्त में से दिए गए राज्य आयोजना परिव्यय में से कई आय वर्गों के लिए विभिन्न समुदाय आवास स्कीमों को तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल. आई.जी. आवास की प्रगति की निगरानी सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत करती है।

जैसी कि शासन के राष्ट्रीय एजेन्डा में कल्पना की गई है, गरीबों तथा उपेक्षितों के लिए आवास निर्माण हेतु लक्ष्य में पर्याप्त बढ़ोत्तरी होगी। एजेन्डा में देश के शहरी क्षेत्रों में प्रति वर्ष 7 लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय एजेन्डा के कार्यान्वयन की पद्धति को राज्य सरकारों/संघ प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श से परखा जाएगा।

(ग) राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान, चालू कार्यक्रमों के अन्तर्गत 2000 ई.डब्ल्यू.एस. तथा 1000 एल. आई.जी. मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य एजेन्सियों द्वारा राज्य योजना संसाधनों तथा आवास व नगर विकास निगम लि. (हुडको) तथा अन्य आवास वित्त संस्थानों से ऋण लेकर निर्माण शुरू करने की सम्भावना है। राजस्थान के लिए 7 लाख मकानों की कार्य योजना का अतिरिक्त लक्ष्य राज्य सरकार से परामर्श के बाद निर्धारित किया जाएगा।

Blocking main road of J-Block in Dilshad Garden

560. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that more than 100 Jhuggis have been built in front of shops during the last three months, blocking the main road of J-Block in Dilshad Garden in North-East Delhi;

(b) whether Government are aware that residents of Dilshad Garden have lodged several complaints to the police against the encroachers of public land;

(c) if so, the reasons for not initiating action against the encroachers of public land and whether responsibility in this regard is proposed to be fixed on the S.H.O. of that area; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) Delhi Development Authority and Delhi Police have reported that there is no J-Block in Dilshad Garden, Delhi. However, there is a J&K Pocket in Dilshad Garden, where no jhuggi exists.

(b) Delhi Police has reported that no complaints against jhuggi dwellers of Dilshad Garden has been received.